नव भारत
1934 से

कृषिभूमि का 4 गुना मुआवजा

- आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- अब तक केवल दो गुना राशि देने का था प्रावधान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 अगस्त. मप्र में अब यदि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि की जरुरत है और यह भूमि किसान परस्पर सहमति से राज्य सरकार को दे देते हैं तो ऐसे मामले में राज्य सरकार किसानों को चार गुना तक मुआवजा देगी.

मंगलवार को कैबिनेट ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. अब तक ऐसे मामलों में महज दो गुना तक ही राशि देने की प्रावधान था. यदि किसान भूमि देने के लिए राजी नहीं होते, तो ऐसे मामलों में यदि सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना पड़ा तो फिर कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से महज दो गुना राशि ही दिया जाएगा.

इस तरह राज्य सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बिना किसी विवाद के कृषि भूमि हासिल करने के लिए ज्यादा मुआवजा देकर किसानों की शिकायत को दूर करने की कोशिश कर रही है. दरअसल कई मामलों में किसान जमीन देने के बजाय अदालत की राह पकड़ लेते हैं, इससे सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं का काम अटक जाता है. परियोजनाओं में देरी के कारण लागत बढ़ जाती है, इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ता है. लिहाजा राज्य सरकार अब किसानों को ज्यादा मुआवजा देने तैयार हो गई है.

कैबिनेट ने मप्र. सड़क विकास निगम द्वारा नाबार्ड इंफ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस से 4 हजार 600 करोड़ रुपये का ऋण के लिए राज्य सरकार गारंटी देगी. इस ऋण से 12 सड़कों का निर्माण किया जाएगा.

3960 करोड़ रुपए में बनेगा सिवनी-बालाघाट फोरलेन

सिवनी-बालाघाट 91.64 किमी सड़क अब फोरलेन में अपग्रेड होगा. कैबिनेट ने इस संबंध में पेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ निर्माण और अन्य जरुरी कार्यों के लिए कुल 3,960 करोड़ 9 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है.

22 प्रमुख सड़कों का हस्तांतरण एमपीआरडीसी को किया जाएगा

राज्य की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व हस्तांतरण नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को किया जाएगा. निगम का संचालक मंडल राज्य सरकार के पक्ष में अपनी शेयर जारी करेगा. इस ऋण के ब्याज और ऋण का भुगतान हस्तांतरित मार्ग से प्राप्त टोल संग्रहण और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि से किया जाएगा.

मंत्रिमंडल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

- निर्धन और कमजोर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित 19 योजनाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए 1 हजार 740 करोड़ रूपये की स्वीकृति.
- मप्र धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय उज्जैन के संचालन के लिए 244 पदों की स्वीकृति.
- राज्य कम्प्यूटर सेक्युरिटी इंसीडेंट/रेसपान्स ऑपरेशन सेन्टर की स्थापना संबंधी योजना के लिए 80 करोड़ रूपये मिलेंगे.
- अतिथि गृह के उन्नयन और संचालन के लिए पांच वर्ष में 250 करोड़ 67 लाख रूपये मिलेंगे.
- भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिवर्तित धाराओं में कार्यवाही के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मप्र को अधिकृत करने के लिए अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति
- महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 (दृष्टिबाधित) में प्रदाय प्रोत्साहन राशि 78 लाख की प्रतिपूर्ति खिलाडियों को प्रोत्साहन मद से करने की कार्योत्तर स्वीकृति.

भागीरथपुरा कांड की 600 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश

- रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आपत्ति, सुरक्षित रखा आदेश
- निगम, आईडीए, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुटाए रिकॉर्ड

नवभारत न्यूज

इंदौर, 25 अगस्त . भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की 600 से ज्यादा पन्नों की न्यायिक जांच रिपोर्ट मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष पेश की गई. रिपोर्ट फिलहाल सीलबंद है.

इसे सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति सामने आने के बाद कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही सामने आएगा कि जांच आयोग ने घटना के लिए किन कारणों और जिम्मेदारियों को लेकर क्या निष्कर्ष दिए हैं.

भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने और 36 लोगों की मौत के बाद मामले की न्यायिक जांच कराई गई थी. जांच आयोग ने नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग समेत संबंधित विभागों से रिकॉर्ड जुटाए. प्रभावित लोगों के बयान दर्ज किए गए. इसके अलावा घटना के दौरान राहत, उपचार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई. मंगलवार को सुनवाई के दौरान रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मुद्दे पर आपत्ति दर्ज कराई गई.

इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. अब कोर्ट के आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 600 से अधिक पन्नों की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं और उसमें जांच आयोग ने घटना को लेकर क्या निष्कर्ष निकाले हैं.

कई अफसरों की भूमिका भी जांच के दायरे में...

जांच के दौरान तत्कालीन निगम कमिश्नर दिलीप यादव, तत्कालीन अपर कमिश्नर रोहित सिसोनिया, कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव और स्थानीय पार्षद कमल वाघेला समेत कई अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रही. हालांकि, रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए इनमें से किसी की जिम्मेदारी तय होने की पुष्टि नहीं हुई है.

कूनो पार्क से मादा चीता 'निर्वा' लापता

- एक सप्ताह से अधिक समय से नहीं मिला सुराग
- रेडियो कॉलर खराब होने से निगरानी पर उठे सवाल

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 25 अगस्त . कूनो नेशनल पार्क से मादा चीता 'निर्वा' के एक सप्ताह से अधिक समय से लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है.

मामले में वन्यजीवों की निगरानी और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तक शिकायत पहुंचने की बात सामने आई है.

सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आया मामला

वन्यजीव विशेषज्ञ और आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर निर्वा के लापता होने की जानकारी सार्वजनिक की. उनके अनुसार निर्वा दो शावकों की मां है और उसके गले में लगा रेडियो कॉलर लंबे समय से खराब बताया जा रहा है. इसके चलते उसकी गतिविधियों और सटीक लोकेशन की निगरानी में परेशानी सामने आई. मामले ने कूनो में वन्यजीवों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. निर्वा की तलाश और उसकी स्थिति को लेकर वन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर अब नजर बनी हुई है. साथ ही रेडियो कॉलर के खराब होने की अवधि और निगरानी व्यवस्था से जुड़े तथ्यों की जांच की मांग भी उठ रही है.

नदी पार कर स्कूल जाते थे 40 बच्चे, प्रभारी प्राचार्य हटाए

- शिक्षा विभाग ने दिए सुरक्षित आवागमन के निर्देश
- वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

उमरिया, 25 अगस्त . जिले के करकेली विकासखंड के मानिकपुर गांव से बिलासपुर हाईस्कूल जाने वाले करीब 40 बच्चों के जान जोखिम में डालकर बड़की नदी पार करने का मामला सामने आया है.

बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगह पानी बच्चों की कमर तक पहुंच रहा था. इसके बावजूद बच्चे रोजाना नदी पार कर स्कूल पहुंचते थे. छोटे बच्चों को उनके माता-पिता कंधे पर बैठाकर नदी पार कराते थे. बच्चों के नदी पार करने का वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बीएस बरकड़े ने मामले का संज्ञान लिया और स्कूल प्रबंधन को सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. निर्देशों के बावजूद बच्चों को नदी के रास्ते घर जाने देने पर प्रभारी प्राचार्य अमित पटेल को पद से हटा दिया गया.

शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने और निगरानी के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं.

पुल का इंतजार अब नाराजगी में बदला

बालाघाट. जिले की सुसवा पंचायत के हुड्डू टोला और सेकी टोला के ग्रामीणों का नाले पर पुल का इंतजार अब नाराजगी में बदल गया है. करीब 500 ग्रामीणों की आबादी वाले इन गांवों में बारिश के दौरान नाले में पानी बढ़ने से आवागमन मुश्किल हो जाता है. स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है. ग्रामीणों के अनुसार अगस्त 2023 में जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान आरईएस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पुल का एस्टीमेट तैयार कर जल्द निर्माण शुरू कराने का लिखित आश्वासन दिया था.

एक नजर में

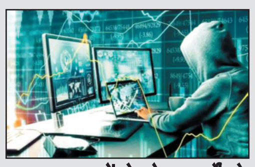

साइबर ठगों ने दो बुजुर्गों से की 4.35 लाख की ठगी

ग्वालियर. साइबर ठगों ने ग्वालियर में दो बुजुर्गों को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से कुल 4 लाख 34 हजार 976 रुपए निकाल लिए. एक मामले में रिटायर्ड लाइब्रेरी हेड के दो बैंक खातों से 2.35 लाख रुपए निकाले गए, जबकि दूसरे मामले में 74 वर्षीय बुजुर्ग को एसबीआई अधिकारी बनकर 'सीनियर सिटीजन पेंशन कार्ड' बनाने का झांसा दिया और लिंक भेजकर 1.99 लाख ठग लिए गए.

मऊगंज पेट्रोल कांड में लापरवाह मुंशी निलंबित

रीवा. मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र के अलोहा गांव में चार युवकों को पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पीड़ितों की शिकायत दर्ज नहीं करने और घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह को एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. घटना सोमवार रात की बताई गई है. चार युवकों पर गांव के ही रामरहीस ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. घटना में अजहरुद्दीन उर्फ राजू गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि मोहम्मद सद्दाम, अनवर अली और अतीक अहमद भी घायल हुए.

भोजशाला के पास नमाज के विरोध में धार बंद

- हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज़

धार, 25 अगस्त . पुरातन भोजशाला परिसर के पास मुस्लिम समाज द्वारा शुक्रवार को नमाज अदा किए जाने के विरोध में मंगलवार को धार में मुकम्मल बंद रहा.

हिंदू पक्ष की ओर से इसे लेकर एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा गया. हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय द्वारा पुरातन भोजशाला परिसर, जो कि माता वांग्देवी का मंदिर है, के पास शुक्रवार को नमाज अदा किया जाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी है.

धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला के पास मुस्लिमों द्वारा हर शुक्रवार को नमाज अदा किए जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है. इसी के चलते विरोध में हिंदू पक्ष द्वारा मंगलवार को धार बंद का आह्वान किया गया. संपूर्ण धार जिला मुख्यालय में कोई भी दुकान खुली नहीं दिखाई दी. सड़कों पर पुलिस और प्रशासन की चहल कदमी देखी गई. हिंदू संगठनों द्वारा भोजशाला के पास मुस्लिम पक्ष द्वारा नमाज अदा किए जाने के विरोध में कलेक्टर राजीव रंजन मीना को एक ज्ञापन भी सौंपा.

इसमें यह मांग की गई है कि हिंदू पक्ष की भावनाओं के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के भी पालन में सर्वे नंबर 596 पर शुक्रवार को मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करवाई जाए.

इंडिगो फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में किया भर्ती

नवभारत न्यूज़

इंदौर, 25 अगस्त. इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में मंगलवार सुबह एक यात्री की तबीयत बिगड़ने पर एयरपोर्ट पर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई.

सुबह करीब 6:20 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से मेडिकल असिस्टेंस की सूचना मिलने पर एयरपोर्ट के डॉक्टर को तत्काल सूचित किया गया. करीब 6:30 बजे दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट 6श्व 6490 के आगमन पर यात्री रोहित बेदी को फ्लाइट से उतारकर व्हीलचेयर के माध्यम से एमआई रूम लाया गया. यहां डॉक्टर ने यात्री का प्राथमिक निरीक्षण किया और उनसे बातचीत की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यात्री को मिर्गी का दौरा पड़ा था. यात्री को आवश्यक प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सकीय सहायता दी गई. उपचार के लिए इंडिगो स्टाफ की मौजूदगी में एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें बांठिया हॉस्पिटल भेजा गया.

जमीन के नाम पर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 62.50 लाख की ठगी

चार साल बाद एफआईआर दर्ज

इंदौर, 25 अगस्त . राजेंद्र नगर क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 62.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.

बिजलपुर में कृषि भूमि खरीदने का झांसा देकर वर्ष 2021 से जून 2022 के बीच यह रकम ली गई, लेकिन न जमीन की रजिस्ट्री हुई और न ही पीड़ित को कब्जा मिला. करीब चार साल तक शिकायत के बाद अब पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है.

रिटायर्ड बैंक मैनेजर अतुल पंडित ने शिकायत में बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद निवेश के लिए उनके रिश्तेदार हरीश आदले ने बिजलपुर में कृषि भूमि खरीदने का प्रस्ताव दिया था. उसने जमीन का भविष्य में व्यावसायिक उपयोग होने और कीमत बढ़ने की बात कहकर उन्हें भरोसे में लिया. इसके बाद अतुल ने अलग-अलग किश्तों में आरोपियों को कुल 62.50 लाख रुपए दिए.

संदिग्ध घुसपैठियों को बांग्लादेश सीमा पर ले गई क्राइम ब्रांच

- गृह मंत्रालय के आदेश पर दस्तावेजों और पहचान की हुई जांच
- जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत से किया जाएगा डिपोर्ट

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 25 अगस्त . ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया के तहत ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है.

पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों से चार बच्चों समेत 13 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था. करीब 20 दिन तक पूछताछ और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सोमवार देर रात विशेष पुलिस टीम सभी को सुरक्षा घेरे में लेकर बांग्लादेश सीमा के लिए रवाना हुई.

पुलिस के अनुसार, ये लोग ग्वालियर के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में झुग्गियों में कथित तौर पर पहचान छिपाकर रह रहे थे. सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने 3-4 अगस्त की रात चिन्हित ठिकानों पर दबिश देकर महिला और बच्चों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया था.

कृषि क्षेत्र में ग्वालियर तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड : सीएम

'बलराम कृषि महोत्सव' का आयोजन, किसानों और मेधावी बच्चों का सम्मान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 25 अगस्त . मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर कृषि के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा से भी आगे पहुंचेगा.

सरकार ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने में हरसंभव सहयोग करेगी. मुख्यमंत्री डबरा तहसील प्रांगण में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' को भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ग्वालियर शिक्षा, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी है. ग्वालियर की पहचान तानसेन, गजक के साथ किसानों और जवानों से भी है. उन्होंने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और उन्नत पशुपालन अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों की आर्थिक उन्नति का प्रभावी माध्यम है.

रबी फसलों के लिए दिन में भी बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं और चना जैसी रबी फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने किसानों से जमीन सुरक्षित रखने और विवाह में अनावश्यक खर्च से बचते हुए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने की अपील की. डबरा मंडी प्रांगण में आयोजित महोत्सव में प्रगतिशील किसानों और उनके मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया.

छात्रा से दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर, 25 अप्रैल . शाहपुरा क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है.

पुलिस के अनुसार 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 18 वर्षीय युवक ने दिसंबर 2025 में छात्रा को घूमाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो के जरिए उसे लगातार धमकाने का आरोप है. मुख्य आरोपी के चार साथियों को वीडियो की जानकारी हुई. आरोप है कि उन्होंने भी छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके साथ यौन शोषण किया. डर और धमकी के कारण छात्रा कई महीनों तक घटना की जानकारी परिवार को नहीं दे सकी. बताया गया कि 20 अगस्त को आरोपी छात्रा को कार में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया गया. इसके बाद छात्रा ने मंगलवार को अपने परिजनों को पूरी घटना बताई. परिजन उसे शाहपुरा थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

कुछ ही घंटों में गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर मुख्य आरोपी निखिल सिंह राजपूत, संदीप चौहान, प्रशांत पटेल, सौरभ सिंह और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. मामले की जांच जारी है.

आदेश | **जिला या अधीनस्थ अदालत में ट्रांसफर करने की मांग हाईकोर्ट से निरस्त**

ब्रिटेन के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड का एग्जीक्यूशन हाईकोर्ट में होगा

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 25 अगस्त . मप्र हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में पारित विदेशी आर्बिट्रेशन अवार्ड के एग्जीक्यूशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार विदेशी आर्बिट्रेशन अवार्ड को मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47 और 48 के तहत लागू करने योग्य घोषित कर दिया जाता है, तो धारा-49 के तहत वह उसी हाईकोर्ट की डिक्री माना जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन भी हाईकोर्ट में ही किया जा सकता है. जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने मित्तल एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड की उस आपत्ति को निरस्त कर दिया, जिसमें अवार्ड को एग्जीक्यूशन के लिए जिला न्यायालय या अधीनस्थ अदालत भेजने की मांग की गई थी. दरअसल मामला जीएएफटी के तहत 26 अगस्त 2022 को ब्रिटेन में पारित आर्बिट्रेशन अवार्ड से जुड़ा है. विवाद दो हजार मीट्रिक टन आर्गेनिक सोयाबीन की सप्लाई को लेकर राबर्ट मोशर ट्रांसपोर्ट इंक और मित्तल एग्रीटेक के बीच हुआ था. अवार्ड एकमात्र आर्बिट्रेटर जूली हाकिंस ने पारित किया था. एग्जीक्यूशन के दौरान मित्तल एग्रीटेक ने सीपीसी की धारा 38 और 39 का हवाला देकर मामले को जिला या सक्षम वाणिज्यिक न्यायालय भेजने की मांग की.

हालांकि, व्यावहारिक कठिनाई होने पर सीपीसी की धारा-39 के तहत डिक्री को सक्षम अदालत में भेजा जा सकता है. फिलहाल कोर्ट ने आदेश 21 के तहत एग्जीक्यूशन हाईकोर्ट में ही जारी रखने के निर्देश दिए.

> वहीं, अवार्ड धारक की ओर से अधिवक्ता शिवांश सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी अवार्ड के प्रवर्तन और एग्जीक्यूशन के लिए अलग-अलग कार्यवाही आवश्यक नहीं है. हाईकोर्ट ने माना कि एक ही कार्यवाही में पहले अवार्ड की प्रवर्तनीयता तय करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है. इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है.

डबरा हाईवे पर 5 गौवंश की मौत के बाद हंगामा

बलराम कृषि महोत्सव की बसें भी रोकीं

ग्वालियर, 25 अगस्त. डबरा हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पांच गौवंश की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ.

घटना से आक्रोशित गौसेवकों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने परशुराम चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा.

जानकारी के अनुसार डबरा हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पांच गौवंश की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गौसेवक और संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने हादसे के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई और सड़क पर गौवंश की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की.